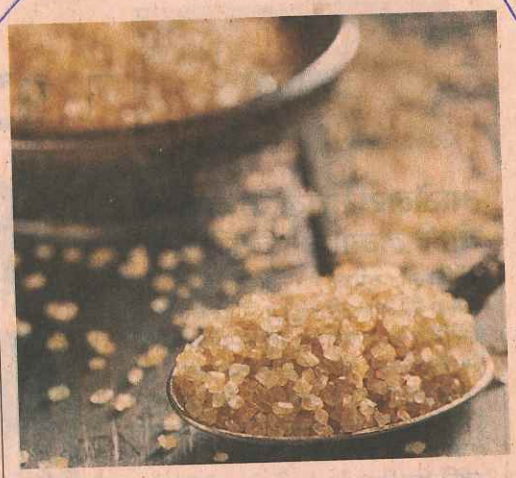

ज्यादा रॉ शुगर एक्सपोर्ट करेंगी महाराष्ट्र की मिलें

पेराई सीजन के पहले दो महीनों में मिलर्स रॉ शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं

[जयश्री भोसले | पुणे]

भारत सरकार की 50 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट अनिवार्य करने की घोषणा से आईसीई पर शुगर फ्यूचर्स में गिरावट आई, वहीं इस पेराई सीजन के पहले दो महीनों में महाराष्ट्र के मिलर्स रॉ शुगर का अधिकतम एक्सपोर्ट करने की तैयारी में हैं। यह सीजन 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मिलर्स इस बात से काफी खुश हैं कि उन्होंने जितनी मदद मांगी थी, उससे ज्यादा मिली।

गन्ने की कीमत के भुगतान में सहायता राशि 55 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 138 रुपये प्रति टन कर दी गई, जबकि इंडस्ट्री की डिमांड 110 रुपये प्रति टन की थी। मिल से बंदरगाहों की दूरी के अनुपात में शुगर एक्सपोर्ट के लिए करीब 5538 करोड़ रुपये की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी गई है।

नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नायकवारे ने कहा, 'एक्सपोर्ट होने वाली शुगर पर मिलर्स को मिलने वाली रिलीफ 7.70 रुपये से बढ़ाकर 9.15 रुपये प्रति किलो की गई थी। अब इसको 11.30 रुपये प्रति किलो किया गया है।' सरकार की तरफ से रॉ के साथ ही सफेद और रिफाइंड शुगर के लिए भी सहायता राशि है। ऐसे में इंडस्ट्री रॉ शुगर के एक्सपोर्ट पर फोकस करेगी। वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA) के प्रेसिडेंट बी बी थोंब्रे ने कहा, 'पहले दो महीनों में मिलें अधिकांश रॉ शुगर का उत्पादन और एक्सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इस दौरान शुगर का उत्पादन कम रहता है।'

> केंद्र सरकार की मदद के बावजूद अभी 4 से 4.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घाटे की भरपाई की जरूरत है

मिलों से अधिक एक्सपोर्ट की अपील करते हुए महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के वाइस चेयरमैन जयप्रकाश डांडेगांवकर ने कहा, 'हमें उत्तर प्रदेश की मिलों के स्थानांतरणीय कोटा पर भी शुगर का एक्सपोर्ट करना चाहिए।' महाराष्ट्र की शुगर मिलें राज्य सरकार से फाइनेंशियल मदद के लिए लॉबिंग करेंगी। दरअसल, केंद्र सरकार की मदद के बावजूद अभी 4 से 4.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घाटे की भरपाई की जरूरत है। इधर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना पैकेज घोषित किया है। अब राज्य की इंडस्ट्री केंद्र सरकार से बिना इंटरेस्ट के सॉफ्ट लोन मिलने के इंतजार में हैं, ताकि वह बैंक लोन की शार्ट मार्जिन को कवर कर सकें।

इससे पहले जून में 4047 करोड़ रुपये की मदद के ऐलान को मिलाकर इस साल अब तक केंद्र सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को 9585 करोड़ रुपये की कुल मदद दी है।

The Economic Times
28-09-18.